

नड्डा-एम्स

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में अब आठ सौ 19 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्नातक चिकित्सा सीटें अब 51 हजार से बढ़कर एक लाख 29 हजार हो गई हैं। आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, नई दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 78 हजार हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिकित्सा विज्ञान, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एम्स ने स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता और रोगियों की देखभाल में अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

चंद्र कुमार

पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के ढगवार में मिल्क प्लांट पंदेश का सबसे उन्नत दुग्ध संयंत्र होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करेगा। चंद्र कुमार ने संयंत्र के कार्यों के प्रगति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दुग्ध संयंत्र की क्षमता डेढ़ लाख लीटर प्रति दिन की होगी और इस पर लगभग 2 सौ 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पशुपालन मंत्री ने बताया कि अभी तक लगभग 41 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गाय का दूध 50 रुपये और भैंस का दुध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अलावा पशुपालकों से गोबर की खाद 3 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जा रही है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा।

जीएसटी सुधार

वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आवास क्षेत्र में नई जीएसटी दरें नागरिकों के लिए मददगार साबित हो रही हैं।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने विभिन्न निर्माण सामग्रियों में कर कटौती कर इन्हें अधिक किफायती बना दिया है, जिससे आवास और निर्माण क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल रहा है। नए कर ढांचे में मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है, जिससे फिनिशिंग और फ्लोरिंग की लागत में कमी आई है। इसी प्रकार सीमेंट पर कर की दर को 28% से घटकर 18% कर दिया गया है, जिससे निर्माण की कुल लागत में कमी आई है। वहीं, सैंड लाइन ईंटों पर भी जीएसटी को 12% से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया

है। इन सुधारों से न केवल आवास और बुनियादी ढांचा विकास अधिक किफायती हो रहा है, बल्कि निर्माण क्षेत्र में सतत विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी जा रही राहत राशि का हिसाब राज्य सरकार को लोगों को देना चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले अढ़ाई वर्षों में आपदा के लिए केन्द्र द्वारा दी गई 5 हजार 5 सौ करोड़ रुपये की धन राशि का 10वां हिस्सा भी राज्य सरकार आपदा प्रभावितों पर खर्च नहीं कर पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 15 सौ करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल को हर हाल में मिलेगा और राज्य सरकार को इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में हजारों घर नष्ट हो गए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के बजाए मुख्यमंत्री व उनके मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य पथ परिवहन निगम में अनियमितताओं के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनियमितता के लिए चालकों व परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है।
